Test Cloud

Daily करेंट अफेयर्स

02 सितम्बर 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. जॉर्ज कुरियन ने केरल में अल्पसंख्यक मछुआरों को सशक्त बनाने के लिए 'मत्स्य शक्ति' का शुभारंभ किया।

अगस्त 2025 में, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय (MoFAH&D) और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय (MoMA) के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केरल के तिरुवनंतपुरम में "मत्स्य शक्ति" परियोजना का शुभारंभ किया। एक साल तक चलने वाली इस पहल का उद्देश्य प्रशिक्षण, कौशल विकास और उद्यमिता सहायता के माध्यम से अल्पसंख्यक मछुआरा समुदायों को सशक्त बनाना है।

- **यह परियोजना प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS) योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही है, जिससे हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए आजीविका में वृद्धि और टिकाऊ मत्स्य पालन प्रथाओं को सुनिश्चित किया जा सके।**

- **इस परियोजना के कार्यान्वयन में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (MoMA) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (ICAR-CMFRI) के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर शामिल हैं। केरल स्थित ICAR-CMFRI का विझिंजम क्षेत्रीय केंद्र इस योजना को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करेगा।**

Key Points:-

(i) एक संरचित एक वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम अल्पसंख्यक समुदायों के 690 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करेगा। यह कार्यक्रम क्षेत्र ज्ञान, उद्यमिता और मत्स्य पालन से संबंधित कौशल निर्माण पर केंद्रित होगा, जिससे रोजगार क्षमता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।

(ii) चयनित 690 प्रतिभागियों में से 270 को गैर-पारंपरिक मत्स्य पालन-आधारित कौशलों में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिनमें से 90 को मछली हैचरी उत्पादन और 180 को पिंजरा पालन में मछली पालन की मूल बातें सिखाई जाएँगी। इस विविधीकरण का उद्देश्य केरल में आधुनिक जलीय कृषि पद्धतियों को मज़बूत करना है।

(iii) इसके अतिरिक्त, 420 महिला उम्मीदवारों को नेतृत्व और उद्यमिता कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जिससे वे उद्यम स्थापित और प्रबंधित कर सकेंगी। सभी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि के दौरान वजीफा मिलेगा, जिससे वित्तीय सहायता और समावेशिता सुनिश्चित होगी।

2. IIT हैदराबाद ने भारतीय सेना के SDD के साथ मिलकर 'VIGRAHA' उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया।

30 अगस्त, 2025 को, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद (IITH) ने भारतीय सेना के सिम्युलेटर विकास प्रभाग (SDD) के साथ एक रणनीतिक सहयोग

किया, जिसके तहत 'विग्रह' नामक उत्कृष्टता केंद्र (CoE) की स्थापना की जाएगी - जो AR/VR और उच्च तकनीक अनुप्रयोगों में आभासी, बुद्धिमान, अभूतपूर्व अनुसंधान का संक्षिप्त रूप है।

• इस पहल का उद्देश्य संवर्धित वास्तविकता (AR), आभासी वास्तविकता (VR), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रोबोटिक्स, ड्रोन और मानवरहित प्रणालियों में अनुसंधान को आगे बढ़ाना है, जिससे रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा मिले।

• समझौता ज्ञापन (MoU) पर IITH के निदेशक प्रो. बी.एस. मूर्ति और SDD के वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें ब्रिगेडियर ए.के. चतुर्वेदी, कर्नल हरिओम अहलावत और लेफ्टिनेंट कर्नल अनुपम पोरवाल शामिल हैं, की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। आईआईटीएच में इस पहल का नेतृत्व प्रो. जी. नरहरि शास्त्री और डॉ. शिवा जी कर रहे हैं, जो CoE के प्रमुख अन्वेषक होंगे।

Key Points:-

(i) 'विग्रह' की स्थापना भारत में शैक्षणिक संस्थानों और रक्षा एजेंसियों के बीच बढ़ते तालमेल को रेखांकित करती है। अत्याधुनिक तकनीकों को रक्षा अनुप्रयोगों में एकीकृत करके, इस सहयोग का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाना और रक्षा प्रौद्योगिकी में राष्ट्र की आत्मनिर्भरता में योगदान देना है।

(ii) 'विग्रह' संयुक्त शैक्षणिक कार्यक्रमों, अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं, उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण एवं प्रमाणन, छात्रों के लिए इंटर्नशिप और उन्नत सुविधाओं तक साझा पहुँच को सुगम बनाएगा। इस सहयोगात्मक प्रयास से रक्षा और सामरिक क्षेत्रों में उभरती चुनौतियों का समाधान करने वाले नवीन समाधान सामने आने की उम्मीद है।

(iii) यह साझेदारी भारत के व्यापक रक्षा आधुनिकीकरण लक्ष्यों के अनुरूप है और अकादमिक-रक्षा सहयोग के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उत्कृष्टता केंद्र रक्षा प्रौद्योगिकियों में अग्रणी अनुसंधान और विकास का केंद्र बनने के लिए तैयार है, जो देश की रक्षा क्षमताओं में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

3. भारत ने नोएडा में पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया।

30 अगस्त, 2025 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा में भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया, जिसे ऑप्टिमस इंफ्राकॉम ने अमेरिकी सामग्री प्रौद्योगिकी अग्रणी कॉर्निंग इंकॉर्पोरेटेड के सहयोग से स्थापित किया है - जो देश की इलेक्ट्रॉनिक्स आत्मनिर्भरता यात्रा में एक ऐतिहासिक कदम है।

• यह कारखाना भारत की मेक इन इंडिया पहल के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह आवश्यक मोबाइल उपकरण घटकों - विशेष रूप से स्क्रीन के लिए टेम्पर्ड ग्लास - के स्वदेशी उत्पादन को सक्षम बनाता है, जिससे पहले आयात पर निर्भर घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को सशक्त बनाया जा सकेगा।

• यह सुविधा शुरू में 70 करोड़ रुपये के निवेश के साथ स्थापित की गई थी, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 2.5 करोड़ इकाई है और 600 से अधिक लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होगा।

• दूसरे चरण में, जिसमें अतिरिक्त 800 करोड़ रुपये शामिल होंगे, घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों के लिए क्षमता को बढ़ाकर 20 करोड़ इकाई प्रति वर्ष किया जाएगा।

Key Points:-

(i) इस गठबंधन के तहत, टेम्पर्ड ग्लास का उत्पादन विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त "कॉर्निंग द्वारा इंजीनियर्ड" लेबल के तहत किया जाता है, और ऑप्टिमस ने कॉर्निंग ग्लास का उपयोग करके भारत में निर्मित पहला प्रीमियम स्क्रीन प्रोटेक्टर ब्रांड, राइनोटेक लॉन्च किया है। राइनोटेक उन्नत सुविधाएँ प्रदान करता है जैसे कि एंटी-माइक्रोबियल सुरक्षा, प्रामाणिकता के लिए फॉग-मार्क, और एक साल की असीमित प्रतिस्थापन नीति।

(ii) यह विकास भारत की निम्न-गुणवत्ता वाले आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद करता है, जिससे 20,000 करोड़ रुपये के घरेलू बाजार और 2025 में 400 मिलियन इकाइयों की अनुमानित मांग को पूरा किया जा सकेगा। उत्पाद की विश्वसनीयता को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने गुणवत्ता, एकरूपता और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए "रासायनिक रूप से टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर" के लिए दुनिया का पहला मानक पेश किया।

(iii) उद्घाटन के अवसर पर, मंत्री वैष्णव ने चिप्स से लेकर कवर ग्लास तक, हर आवश्यक मोबाइल कंपोनेंट के निर्माण की भारत की महत्वाकांक्षा पर ज़ोर दिया, जिससे पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण स्वायत्तता की ओर कदम बढ़ाया जा सके। टेम्पर्ड ग्लास सुविधा पिछले एक दशक में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को ₹11.5 लाख करोड़ के उत्पादन और ₹3 लाख करोड़ के निर्यात से आगे बढ़ाने में एक आधारशिला है, जिसका आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

4. भारत ने आदि वाणी लॉन्च की: जनजातीय भाषाओं के लिए देश का पहला एआई-संचालित अनुवादक।

31 अगस्त, 2025 को जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आदि वाणी के बीटा संस्करण का अनावरण किया - जो जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का अग्रणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) संचालित अनुवाद उपकरण है - जिसे संचार अंतराल को पाटने, लुप्तप्राय बोलियों को संरक्षित करने और जनजातीय समुदायों में समावेशी शिक्षा, डिजिटल साक्षरता और शासन का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

• आदि वाणी को जनजातीय गौरव वर्ष पहल के तहत आईआईटी दिल्ली, बिट्स पिलानी, IIT हैदराबाद और IIT नया रायपुर सहित प्रमुख संस्थानों के एक संघ द्वारा झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेघालय में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (TRIs) के साथ विकसित किया गया था - यह समुदाय-संचालित भाषाई ज्ञान के साथ AI विशेषज्ञता का संयोजन करने वाला एक अनूठा सहयोग है।

• Beta एप्लिकेशन वर्तमान में गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, और इसका iOS संस्करण भी जल्द ही आने वाला है। यह हिंदी/अंग्रेजी और आदिवासी भाषाओं, जैसे संताली (ओडिशा), भीली (मध्य प्रदेश), मुंडारी (झारखंड), और गोंडी (छत्तीसगढ़) के बीच रीयल-टाइम टेक्स्ट और स्पीच ट्रांसलेशन को

सक्षम बनाता है। भविष्य के संस्करणों में और भाषाएँ जोड़ने की योजना है।

Key Points:-

(i) आदि वाणी पाठ-से-वाक् रूपांतरण का समर्थन करती है और उपयोगकर्ताओं—जनजातीय छात्रों और शिक्षकों सहित—को हिंदी या अंग्रेजी शैक्षिक सामग्री (जैसे NCERT पाठ्यपुस्तकें) का अपनी मातृभाषा में अनुवाद करने की सुविधा देती है। इसमें सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक सामग्री जैसे लोककथाएँ, मौखिक परंपराएँ, सरकारी योजनाओं की जानकारी और स्वास्थ्य संबंधी सलाह (जैसे, सिकल सेल एनीमिया के बारे में) भी शामिल हैं, जो इसे सीखने और संचार के लिए एक शक्तिशाली माध्यम बनाती हैं।

(ii) यह पहल डिजिटल इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आदि कर्मयोगी अभियान, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और PM जनमन जैसे प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अनुरूप है। यह जनजातीय आबादी के लिए समावेशी सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को संरक्षित करने के लिए संवैधानिक जनादेश (अनुच्छेद 29 और 350 A) को भी मजबूत करता है।

(iii) जनजातीय विकास के लिए एक व्यापक रोडमैप में, मंत्रालय ने आदि वाणी के साथ-साथ आदि संस्कृति - कला, परंपराओं और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए एक पोर्टल - को बढ़ावा देने पर जोर दिया है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी, प्रौद्योगिकी-संचालित रणनीति के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में कम संसाधन वाली भाषाओं के राज्य-स्तरीय दस्तावेजीकरण, शासन संचार और शैक्षिक पहुंच को एकीकृत किया जाएगा।

BANKING & FINANCE

1. RBI ने नियामकीय गैर-अनुपालन के लिए बंधन बैंक पर ₹44.70 लाख का जुर्माना लगाया।

29 अगस्त, 2025 को, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वैधानिक और नियामक अनुपालन में कमियों के लिए बंधन बैंक पर ₹44.70 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया। यह जुर्माना बैंकिंग क्षेत्र में नियामक मानदंडों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए RBI की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- **यह जुर्माना 31 मार्च, 2024 तक बंधन बैंक की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए RBI द्वारा किए गए वैधानिक निरीक्षण के बाद लगाया गया है। निरीक्षण से पता चला कि बैंक ने कुछ कर्मचारियों को कमीशन का भुगतान किया था और उचित ऑडिट ट्रेल्स के बिना खाता डेटा में मैन्युअल हस्तक्षेप किया था, जिससे नियामक मानदंडों के अनुपालन में कमियां हुईं।**

- **RBI ने ज़ोर देकर कहा कि यह जुर्माना वैधानिक और नियामकीय अनुपालन में कमियों के आधार पर लगाया गया था और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं था। यह कड़े नियामकीय निरीक्षण के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली की अखंडता बनाए रखने में आरबीआई की भूमिका को उजागर करता है।**

Key Points:-

(i) RBI के निष्कर्षों के जवाब में, बंधन बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि RBI के

निर्देशों का पालन न करने पर उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। बैंक के प्रबंधन से अपेक्षा की जाती है कि वह पहचानी गई कमियों को दूर करने और अपने अनुपालन ढांचे को मज़बूत करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करे।

(ii) यह जुर्माना अन्य वित्तीय संस्थानों को नियामक मानदंडों का पालन करने और मज़बूत अनुपालन तंत्र बनाए रखने के महत्व की याद दिलाता है। जुर्माना लगाने में आरबीआई का सक्रिय दृष्टिकोण भारतीय बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता और अखंडता सुनिश्चित करने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

ECONOMY & BUSINESS

1. NSO की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में भारत की GDP 7.8% बढ़ी, जो 5 तिमाहियों में सबसे अधिक है और RBI के अनुमानों से अधिक है।

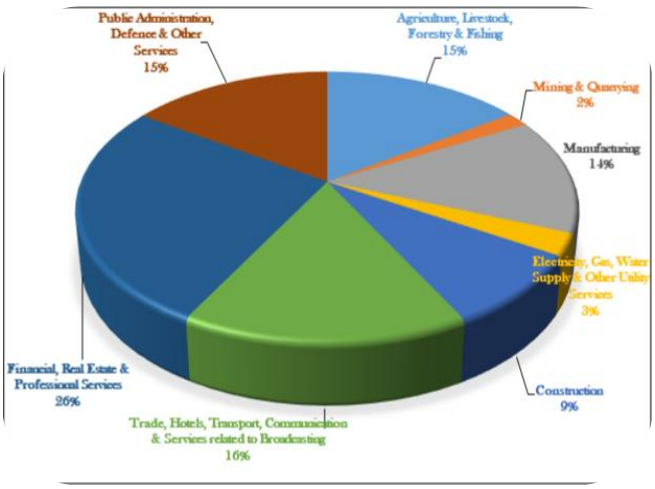

29 अगस्त, 2025 को एक बहुप्रतीक्षित विज्ञप्ति में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने खुलासा किया कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 7.8% की प्रभावशाली वृद्धि हुई, जो पांच तिमाहियों में सबसे तेज तिमाही विस्तार को दर्शाता है।

- **NSO के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2025) में भारत की वास्तविक GDP लगभग ₹47.89 लाख करोड़ रही, जो वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही के ₹44.42 लाख करोड़ से ज़्यादा है, जबकि नाममात्र GDP (मौजूदा कीमतों पर GDP) एक साल पहले के ₹79.08 लाख करोड़ से बढ़कर ₹86.05 लाख करोड़ हो गई। इस मज़बूत विस्तार को पिछली पाँच तिमाहियों में सबसे मज़बूत तिमाही प्रदर्शन माना जा रहा है।**

- **विकास की गति व्यापक थी, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वास्तविक GVA (सकल मूल्य वर्धित) वृद्धि 3.7%, विनिर्माण में 7.7% और निर्माण में 7.6% की वृद्धि दर्ज की गई। सेवा और अन्य क्षेत्रों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे अर्थव्यवस्था के विविध विस्तार कारकों को बल मिला।**

Key Points:-

(i) NSO की 7.8% की वृद्धि दर भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमान 6.5% और निजी क्षेत्र की अधिकांश अपेक्षाओं, लगभग 6.7%, से कहीं अधिक रही, जिससे वित्तीय वर्ष की शुरुआत अनुमान से कहीं ज़्यादा मज़बूत हुई। नीति विश्लेषक इस आश्चर्यजनक वृद्धि का श्रेय अपेक्षा से कम अपस्फीति, अग्रिम सरकारी व्यय और तेज़ घरेलू माँग को देते हैं।

(ii) उत्साहजनक आँकड़ों के बावजूद, अर्थशास्त्री आगाह कर रहे हैं कि यह वृद्धि टिकाऊ नहीं हो सकती। चिंताओं में निर्यात पर मंडराते अमेरिकी टैरिफ का संभावित नकारात्मक प्रभाव, कॉर्पोरेट आय में संभावित मंदी और निवेशकों की सुस्त धारणा शामिल है। कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि नाममात्र GDP वृद्धि वास्तविक GDP से पिछड़ गई है, जिससे लाभप्रदता और राजस्व अनुमान प्रभावित हो रहे हैं।

(iii) इस बीच, वित्त मंत्रालय ने समग्र आर्थिक परिदृश्य को "स्थिर" बताया, जिसमें मज़बूत घरेलू माँग, स्वस्थ

ग्रामीण विकास (अनुकूल मानसून से सहायता प्राप्त) और नियंत्रित मुद्रास्फीति को सहायक कारक बताया। फिर भी, निर्यात संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियाँ, सुस्त ऋण वृद्धि और वैश्विक अनिश्चितताओं को ऐसे क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया गया जिन पर निरंतर गति सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक नीतिगत ध्यान देने की आवश्यकता है।

2. टाटा स्टील ने वैश्विक परिचालन को सुदृढ़ करने के लिए सिंगापुर की सहायक कंपनी TSHPL में 3,100 करोड़ रुपये का निवेश किया।

26 अगस्त, 2025 को, टाटा स्टील लिमिटेड ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सिंगापुर सहायक कंपनी, टी स्टील होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (TSHPL) में नए इक्विटी शेयरों की सदस्यता ली, जिससे लगभग 3,104 करोड़ रुपये (355 मिलियन अमरीकी डॉलर) की हिस्सेदारी हासिल हुई, जो इस वित्तीय वर्ष में इकाई में उसका चौथा पूंजी निवेश था।

- **स्टील प्रमुख ने अपनी सिंगापुर स्थित सहायक कंपनी, टी स्टील होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (TSHPL) में 0.1005 अमेरिकी डॉलर अंकित मूल्य वाले कुल 353,23,38,309 इक्विटी शेयर खरीदे, जिनकी कुल कीमत 355 मिलियन अमेरिकी डॉलर (3,104.03 करोड़ रुपये) है, जैसा कि स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी में बताया गया है।**
- **यह रणनीतिक पूंजी निवेश मई 2025 में स्वीकृत एक बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसके तहत टाटा स्टील का लक्ष्य वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कई किस्तों में TSHPL में 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का निवेश करना है।**
- **विशेष रूप से, यह निवेश 2025 में चौथा निवेश है, इससे पहले फरवरी में ₹10,727 करोड़, जून में ₹1,562.54 करोड़ और जुलाई में ₹1,073.63 करोड़ का फंड ट्रांसफर किया गया था, जो सभी समान प्रति शेयर अंकित मूल्य पर किए गए थे, जो टाटा स्टील की निरंतर विदेशी विस्तार रणनीति को रेखांकित करता है।**

Key Points:-

(i) नवीनतम इक्विटी अभिदान TSHPL को पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी सहायक कंपनी के रूप में मजबूती से बनाए रखता है, जिससे बढ़ते भू-राजनीतिक व्यापार तनाव और संभावित टैरिफ कार्रवाइयों के बीच टाटा स्टील की वैश्विक उपस्थिति मजबूत होती है।

(ii) इस निवेश के साथ, टाटा स्टील ने वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही के लिए मजबूत वित्तीय रिपोर्ट दी, जिसमें 2,007 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ हुआ - जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में दर्ज 918.6 करोड़ रुपये से दोगुना से अधिक था - और 53,178 करोड़ रुपये का राजस्व, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.9% की मामूली गिरावट है, जो परिचालन लचीलापन को उजागर करता है।

MOUs and Agreement

1. डाक विभाग ने डिजीपिन सेवाओं को बढ़ाने के लिए मैपमाईइंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

भारत के डिजिटल बुनियादी ढाँचे की दिशा में एक बड़ी प्रगति करते हुए, डाक विभाग, संचार मंत्रालय और मैपमाईइंडिया-मैपल्स ने डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर (DIGIPIN) को मैपल्स के भू-स्थानिक प्लेटफ़ॉर्म के साथ एकीकृत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। 29 अगस्त, 2025 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित यह समझौता, पूरे देश में एड्रेस-एज़-ए-सर्विस (AaaS) को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

• 29 अगस्त, 2025 को नई दिल्ली में, संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग (DoP) ने एक प्रमुख भारतीय भू-स्थानिक और डिजिटल मानचित्रण फर्म, मैपमाईइंडिया-मैपल्स के साथ एक रणनीतिक साझेदारी को औपचारिक रूप दिया।

• इस समझौता ज्ञापन की अध्यक्षता डाक विभाग के सदस्य (संचालन) श्री हरप्रीत सिंह और मैपमाईइंडिया-मैपल्स के सह-संस्थापक और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राकेश वर्मा ने की, जिससे भू-स्थानिक सेवाओं में डिजिपिन एकीकरण के राष्ट्रव्यापी रोलआउट के लिए मंच तैयार हो गया।

• इस सहयोग से मैपमाइइंडिया को भारतीय डाक के अत्याधुनिक आधार मानचित्रों और भू-स्थानिक डेटासेट तक पहुँच प्राप्त होगी, ताकि उन्हें "अपना डिजिपिन जानें" एप्लिकेशन और इसके प्रमुख मैपल्स ऐप में एकीकृत किया जा सके। अब नागरिक अपनी सटीक भौगोलिक स्थिति से जुड़े सटीक डिजिपिन कोड जनरेट कर सकेंगे और मैपल्स के माध्यम से उन कोड का उपयोग करके सहजता से खोज या नेविगेट कर सकेंगे।

Key Points:-

(i) डिजिपिन, या डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर, एक अद्वितीय, 10-वर्णीय, अल्फ़ान्यूमेरिक जियो-कोडेड पता पहचानकर्ता है जो पूरे भारत में 3.8 मीटर × 3.8 मीटर (ग्रिड-आधारित) सेल के भीतर उत्पन्न होता है। इसे डाक विभाग ने IIT हैदराबाद, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (NRSC) और ISRO के सहयोग से तैयार किया है, जो सटीक स्थान मानचित्रण प्रदान करता है और भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) दृष्टिकोण का आधार बनता है।

(ii) इंडिया पोस्ट अपने सिस्टम में MapmyIndia के उन्नत मैप API को एम्बेड करता है, जबकि MapmyIndia अपने Mappls ऐप में DIGIPIN जनरेशन को एकीकृत करता है, जो अपार्टमेंट, फ़्लोर और लैंडमार्क जैसी विस्तृत जानकारी के लिए अपने स्वयं के Mappls पिन सिस्टम के साथ लेयर्ड है। यह डुअल-पिन फ्रेमवर्क अंतिम-मील सेवा वितरण, लॉजिस्टिक्स, आपातकालीन प्रतिक्रिया, फिनटेक सटीकता और शहरी नियोजन में उल्लेखनीय सुधार करता है।

(iii) यह पहल डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशनों के अनुरूप एक संप्रभु, भू-स्थानिक रूप से सशक्त डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भारत की महत्वाकांक्षा को पुष्ट करती है। यह नागरिकों, व्यवसायों और सरकारी एजेंसियों को सार्वभौमिक रूप से सुलभ, गोपनीयता-केंद्रित और अंतर-संचालनीय डिजिटल पते प्रदान करके सशक्त बनाती है, और भौतिक-डिजिटल अंतर को प्रभावी ढंग से पाटती है।

2. IHMCL और ICICI बैंक ने गुजरात के चोर्यासी में भारत की पहली मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोलिंग प्रणाली को लागू करने के लिए समझौता किया।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की सहायक कंपनी, भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (IHMCL) ने अगस्त 2025 में भारत की पहली मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोलिंग प्रणाली शुरू करने के लिए ICICI बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह पायलट परियोजना गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (NH-48) पर चोर्यासी शुल्क प्लाजा पर लागू की जाएगी।

- **IHMCL और ICICI बैंक के बीच हुए इस समझौते का उद्देश्य एक बाधा-मुक्त इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली शुरू करके टोल संग्रह में क्रांति लाना है। गुजरात स्थित चोर्यासी शुल्क प्लाजा भारत का पहला पायलट स्थल होगा, जो मैन्युअल टोल संग्रह में होने वाली देरी को कम करेगा और एनएच-48 पर वाहनों की निर्बाध आवाजाही को सक्षम करेगा।**

- **यह MLFF प्रणाली टोल लेनदेन को डिजिटल रूप से संसाधित करने के लिए फास्टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID), स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) कैमरे और वाहन पंजीकरण संख्या (VRN) रीडिंग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करती है। इन तकनीकों का एकीकरण टोल संग्रह में सटीकता सुनिश्चित करता है और मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम रखता है।**

- **गुजरात में चोर्यासी शुल्क प्लाजा के साथ-साथ, हरियाणा में NH-44 पर घरौंदा शुल्क प्लाजा में भी इसी तरह का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना है। यह विस्तार, सरकार की उस रणनीति को दर्शाता है जिसके तहत धीरे-धीरे MLFF प्रणालियों को देश भर में विस्तारित किया जाएगा, जिससे भारत का राजमार्ग नेटवर्क अधिक कुशल और वैश्विक टोलिंग मानकों के अनुरूप बन सकेगा।**

Key Points:-

(i) MLFF टोलिंग का एक प्रमुख लाभ यह है कि वाहनों को टोल बूथों पर रुकने की आवश्यकता नहीं होती। यह सुविधा भीड़भाड़ को कम करती है, यात्रा के समय को कम करती है, ईंधन की खपत को कम करती है और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने में मदद करती है, जिससे आर्थिक और पर्यावरणीय दक्षता दोनों में योगदान मिलता है।

(ii) MLFF प्रणाली को कई डिजिटल भुगतान विधियों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे उपयोगकर्ता की सुविधा और तेज़ प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। संपर्क रहित टोल संग्रह का लाभ उठाकर, यह डिजिटल इंडिया के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है और राजमार्ग संचालन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।

(iii) स्केलेबिलिटी इस परियोजना की एक और प्रमुख विशेषता है। IHMCL और NHAI भविष्य में देशव्यापी कार्यान्वयन के लिए चोर्यासी और घरौंदा पायलट परियोजनाओं को मानक के रूप में उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। सफल होने पर, इस मॉडल को भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू किया जाएगा, जिससे टोल प्रबंधन में बदलाव आएगा और सड़क परिवहन के बुनियादी ढाँचे में सुधार होगा।

3. केल्ट्रॉन ने उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति के लिए जिम्बाब्वे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

29 अगस्त, 2025 को, केरल सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (PSE), केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (KELTRON) ने ज़िम्बाब्वे के साथ अपने उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। केरल के कोच्चि में आयोजित एक कार्यक्रम में इस समझौते को औपचारिक रूप दिया गया।

- **इस समझौता ज्ञापन पर केरल के उद्योग मंत्री पी राजीव और ज़िम्बाब्वे के उद्योग एवं वाणिज्य उप मंत्री राजेश कुमार इंदुकांत मोदी ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत शुरुआती आपूर्ति में केल्ट्रॉन द्वारा निर्मित 3,000 कोकोनिक्स लैपटॉप शामिल होंगे।**

- **यह समझौता लैपटॉप के अलावा ट्रैफ़िक लाइट, सौर ऊर्जा प्रणालियों और ज़िम्बाब्वे के बाज़ार के लिए केलट्रॉन द्वारा निर्मित अन्य उत्पादों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर ज़ोर देता है। यह विस्तार केरल की अपने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने की रणनीति के अनुरूप है।**

Key Points:-

(i) उत्पाद आपूर्ति के अतिरिक्त, यह समझौता क्षमता निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें जिम्बाब्वे में एक कौशल विकास केंद्र, एक ज्ञान-साझाकरण केंद्र और एक असेंबली इकाई की स्थापना शामिल है।

(ii) इन पहलों से स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलने, तकनीकी कौशल में वृद्धि होने तथा उत्पादन को समर्थन मिलने की उम्मीद है।

(iii) यह समझौता ज्ञापन प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और कौशल विकास के क्षेत्र में भारत-अफ्रीका सहयोग को बढ़ावा देते हुए अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करने में केरल की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. थाईलैंड की कैबिनेट ने राजनीतिक उथल-पुथल के बीच फुमथम वेचायाचाई को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया।

3 जुलाई, 2025 को एक संक्रमणकालीन कदम उठाते हुए, थाईलैंड के मंत्रिमंडल ने उप-प्रधानमंत्री और गृह मंत्री फुमथम वेचायाचाई को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया। संवैधानिक न्यायालय ने नैतिक उल्लंघनों के लिए प्रधानमंत्री पैतोंगटार्न शिनावात्रा को निलंबित करने का फैसला सुनाया था। यह फैसला बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता के बीच शासन की निरंतरता सुनिश्चित करता है।

- **यह नियुक्ति बैंकॉक के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित एक विशेष कैबिनेट बैठक के दौरान हुई,**

जहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री चुसाक सिरिनिल ने फुमथम की नियुक्ति की घोषणा की। डॉ. प्रोमिन लेर्टसुरीदेज को भी प्रधानमंत्री का महासचिव नियुक्त किया गया, और कैबिनेट ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किए बिना स्थिरता बनाए रखने के लिए एक स्पष्ट कार्यवाहक ढाँचा तैयार किया।

• 71 वर्षीय फुमथम वेचायाचाई, फ्यू थाई पार्टी के एक वरिष्ठ राजनेता हैं, जिन्होंने पूर्व में उप-प्रधानमंत्री, श्रीथा और पैतोंगटार्न सरकारों में वाणिज्य मंत्री, और गृह एवं रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया है। "बिग कॉमरेड" के नाम से प्रसिद्ध, उन्होंने पहली बार अगस्त 2024 में कुछ समय के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया।

Key Points:-

(i) संवैधानिक न्यायालय का निर्णय अगस्त 2025 के अंत में आया, जब 6-3 के फैसले ने प्रधानमंत्री पैतोंगटार्न शिनावात्रा को सीमा तनाव के बीच लीक हुए फोन कॉल में कंबोडियाई नेता हुन सेन को "चाचा" कहकर नैतिक मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए आधिकारिक तौर पर हटा दिया।

(ii) हालाँकि अब मंत्रिमंडल कार्यवाहक क्षमता में कार्य करता है, फिर भी फुमथम को प्रधानमंत्री के पूर्ण अधिकार प्राप्त थे—जिसमें समिति नेतृत्व और प्रशासनिक नियंत्रण भी शामिल था। हालाँकि, नई दीर्घकालिक नीतियों को नई सरकार के गठन तक स्थगित कर दिया गया था। प्रतिनिधि सभा के सचिवालय ने 3-5 सितंबर, 2025 के लिए एक संसदीय सत्र निर्धारित किया है, जिसमें सांसद एक स्थायी प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए मतदान करेंगे।

(iii) यह नेतृत्व परिवर्तन थाईलैंड की राजनीतिक अनिश्चितता को और गहराता है। यह पार्टी की बदलती गतिशीलता के साथ मेल खाता है—फ्यू थाई और प्रतिद्वंद्वी भूमजैथाई गठबंधन के लिए होड़ में हैं, जबकि प्रमुख पीपुल्स पार्टी समर्थन की शर्तों के रूप में संविधान में संशोधन और चार महीने के भीतर संसद भंग करने के लिए जनमत संग्रह की मांग के साथ सत्ता संतुलन पर काबिज है।

SPORTS

1. भारत ने भूटान में 2025 SAFF अंडर-17 महिला चैम्पियनशिप में अपना दबदबा बनाया और शानदार जीत के साथ खिताब पर कब्जा किया।

29 अगस्त, 2025 को थिम्पू के चांगलिमिथांग स्टेडियम में शानदार प्रदर्शन करते हुए, भारत की अंडर-17 महिला फुटबॉल टीम ने नेपाल को 5-0 से हराकर सैफ (दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ) अंडर-17 महिला चैम्पियनशिप 2025 का खिताब जीता, जिससे अजेय बढ़त हासिल हुई और टूर्नामेंट के इतिहास में उनकी तीसरी जीत दर्ज हुई।

• भारत ने अपने अभियान की शुरुआत 20 अगस्त को नेपाल पर 7-0 की करारी जीत के साथ की, जिससे टूर्नामेंट के आरंभ में उनका दबदबा कायम रहा; अभिस्ता बस्नेत, नीरा चानू लोंगजाम, अनुष्का कुमारी के दो-दो गोल और कप्तान जुलान नोंगमाईथेम के एक गोल की बदौलत मिली इस शानदार जीत ने ग्रुप चरणों में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मंच तैयार कर दिया।

• 20 से 31 अगस्त, 2025 तक भूटान में आयोजित इस चैंपियनशिप में चार टीमें - भारत, नेपाल, बांग्लादेश और मेजबान भूटान - शामिल थीं, जो

थिम्पू के चांगलिमथांग स्टेडियम में डबल राउंड-रॉबिन प्रारूप में प्रतिस्पर्धा कर रही थीं; भारत पांच मैचों में 15 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर रहा, जिससे एक गेम शेष रहते उसने खिताब सुनिश्चित कर लिया।

Key Points:-

(i) भारत का खिताब सुनिश्चित करने वाला मैच 29 अगस्त को नेपाल पर 5-0 की जीत थी, जहां टीम ने हाफ टाइम तक 3-0 की बढ़त बना ली थी; पर्ल फर्नांडीस (2), दिव्यानी लिंडा (2) और नीरा चानू लोंगजाम के गोलों ने जीत सुनिश्चित की, हालांकि बांग्लादेश का भूटान के साथ 1-1 से ड्रॉ रहा, जिसका मतलब था कि भारत के कुल अंक अपराजेय रहे।

(ii) इस आयु वर्ग में यह उनकी तीसरी चैंपियनशिप जीत है, भारत की सफलता ने टूर्नामेंट में 12 मैचों में 53 गोल किए, जिसमें अनुष्का कुमारी शीर्ष स्कोरर (8 गोल) के रूप में उभरीं और अभिस्ता बेसनेट को सबसे मूल्यवान खिलाड़ी नामित किया गया, जिससे सामूहिक जीत में व्यक्तिगत प्रशंसा जुड़ गई।

(iii) भारत अब अपना ध्यान अंतिम राउंड-रॉबिन मुकाबलों पर लगाएगा, जहां उनका सामना 31 अगस्त को बांग्लादेश से होगा; चैंपियनशिप पहले ही सुरक्षित कर लेने के बाद, यंग टाइग्रेसेस का लक्ष्य टूर्नामेंट को अपराजित रहते हुए और एक भी गोल खाए बिना समाप्त करना होगा।

2. ICC और गूगल ने महिला क्रिकेट में प्रशंसकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक साझेदारी की।

29 अगस्त, 2025 को, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने गूगल के साथ एक ऐतिहासिक साझेदारी की घोषणा की - इसे अपना दूसरा वैश्विक महिला-केवल भागीदार नामित किया - गूगल की उन्नत तकनीक का उपयोग करने और प्रशंसकों की पहुंच का विस्तार करने के लिए, दो प्रमुख टूर्नामेंटों से ठीक पहले: ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 और ICC महिला T20 विश्व कप 2026।

- **ICC की ओर से जारी एक औपचारिक मीडिया विज्ञप्ति में बताया गया कि इस सहयोग के तहत गूगल के कई उत्पादों - एंड्रॉयड, गूगल जेमिनी, गूगल पे और गूगल पिक्सल - का उपयोग कर मोबाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक सहज, इंटरैक्टिव पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जाएगा, जो प्रशंसकों को खोज और जश्न की पूरी यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण मैच के क्षणों, खिलाड़ियों और कहानियों के करीब बने रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा।**

- **ICC के चेयरमैन जय शाह ने इस गठबंधन को महिला क्रिकेट के लिए एक मील का पत्थर बताया और कहा कि "गूगल के विश्वस्तरीय नवाचार का उपयोग करके, हम प्रशंसकों के लिए अधिक आकर्षक अनुभव बनाने और खेल को हर जगह लोगों के करीब लाने में सक्षम होंगे," और भविष्य की पीढ़ियों को क्रिकेट को एक ऐसे खेल के रूप में देखने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य पर जोर दिया, जहां वे हैं।**

Key Points:-

(i) गूगल की ओर से, गूगल इंडिया के मार्केटिंग उपाध्यक्ष (VP) शेखर खोसला ने समुदाय और साझा जुनून को बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर प्रकाश डाला और कहा कि यह पहल किसी एक आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य स्थायी, सार्थक जुड़ाव बनाना, खेल को सुलभ बनाना और प्रशंसकों को उनके पसंदीदा खेल से गहराई से जुड़ाव महसूस कराने में मदद करना है।

(ii) यह सहयोग ICC की महिलाओं के खेल को बढ़ाने की व्यापक रणनीति के साथ मेल खाता है - यूनिलीवर को अपने पहले वैश्विक महिला भागीदार के रूप में घोषित करने की उनकी पूर्व की घोषणा के आधार पर - और यह ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 (भारत और श्रीलंका में 30 सितंबर से 2 नवंबर तक आयोजित) और आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 (इंग्लैंड, जून-जुलाई) से कुछ सप्ताह पहले आता है, जो डिजिटल और भौतिक चैनलों में दृश्यता और प्रशंसक विसर्जन में तेजी का संकेत देता है।

3. सात्विक-चिराग ने पेरिस में 2025 BWF विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया।

भारतीय पुरुष युगल जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने पेरिस के एडिडास एरिना में आयोजित 2025 बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। पिछली असफलताओं से उबरते हुए उनके इस सफर ने भारत की पदक जीतने की लय को और बढ़ाया और शीर्ष सम्मानों की उनकी तलाश को फिर से जगा दिया।

- **सात्विक और चिराग ने क्वार्टर फ़ाइनल में अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी, आरोन चिया और सोह वूई यिक की मलेशियाई जोड़ी को सीधे सेटों में—21-12, 21-19—सिर्फ़ 43 मिनट में हरा दिया। यह जीत ख़ास तौर पर राहत देने वाली थी, क्योंकि इसने उसी पेरिस स्टेडियम में हुई ओलंपिक हार की यादें मिटा दीं।**

- **सेमीफाइनल में सात्विक-चिराग की जोड़ी चीन के चेन बोयांग और लियू यी से कड़े मुकाबले में 19-21, 21-18, 12-21 से हार गई। हार के बावजूद, भारतीयों ने अपना सिर ऊँचा रखा और एडिडास एरिना में दुनिया भर के दर्शकों के सामने अपने कौशल और धैर्य का प्रदर्शन किया।**

- **उनका कांस्य पदक इस बात की गारंटी देता है कि 2011 से हर विश्व चैंपियनशिप में कम से कम एक पदक जीतने का भारत का प्रभावशाली सिलसिला बरकरार रहेगा। यह निरंतर प्रगति विश्व बैडमिंटन में भारत के बढ़ते प्रभुत्व और गहराई को दर्शाती है।**

Key Points:-

(i) कोच टैन किम हर ने दोनों खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की और कांस्य पदक को गौरवान्वित क्षण बताया। हालाँकि, उन्होंने स्पष्ट रूप से फिटनेस को सुधार की मुख्य दिशा बताया और ज़ोर देकर कहा कि बेहतर सहनशक्ति उन्हें भविष्य के टूर्नामेंटों में फ़ाइनल में पहुँचा सकती है।

(ii) यह उपलब्धि सात्विक-चिराग के लिए 2022 में टोक्यो में मिली सफलता के बाद दूसरा विश्व चैंपियनशिप कांस्य पदक है। पेरिस में उनके अभियान ने स्वर्ण पदक की उम्मीदों को फिर से जगा दिया है, क्योंकि वे गति बनाए रखने, रणनीतियों को निखारने और शीर्ष बैडमिंटन जगत में ऊँचे लक्ष्य

हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।

AWARDS

1. एजुकेट गर्ल्स ने 2025 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय गैर-लाभकारी संस्था बनकर इतिहास रच दिया।

सफीना हुसैन द्वारा 2007 में स्थापित भारत का गैर-लाभकारी संगठन एजुकेट गर्ल्स, 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया है, जिसे व्यापक रूप से एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। इसने 20 लाख से ज़्यादा स्कूल न जाने वाली लड़कियों तक पहुँच बनाई है और 24 लाख से ज़्यादा बच्चों को उपचारात्मक शिक्षा प्रदान की है, जिससे 30,000 से ज़्यादा गाँवों में ग्रामीण शिक्षा का कायाकल्प हुआ है।

- **2025 में, एजुकेट गर्ल्स प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय गैर-लाभकारी संस्था बनकर एक मील का पत्थर स्थापित करेगी। यह पुरस्कार 1957 में एशिया भर में साहसी नेतृत्व और सेवा के सम्मान में स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार का औपचारिक वितरण 7 नवंबर 2025 को मनीला, फिलीपींस के मेट्रोपॉलिटन थिएटर में होगा।**

- **सफीना हुसैन द्वारा 2007 में स्थापित, एजुकेट गर्ल्स ने राजस्थान के पाली जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत की थी। तब से, यह संगठन 30,000 से ज़्यादा गाँवों में फैल चुका है, 20 लाख से ज़्यादा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद कर चुका है और 24 लाख से ज़्यादा बच्चों को सुधारात्मक शिक्षण सहायता प्रदान कर चुका है। यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित कई भारतीय राज्यों में भी काम करता है।**

- **एजुकेट गर्ल्स 23,000 से ज़्यादा 'टीम बालिका' स्वयंसेवकों द्वारा संचालित एक शक्तिशाली ज़मीनी मॉडल का लाभ उठाता है, जो समुदायों के भीतर स्कूल न जाने वाली लड़कियों की पहचान करने और मौजूदा बुनियादी ढाँचे का उपयोग करके उन्हें सरकारी स्कूलों में लाने के लिए काम करते हैं। दो प्रमुख पहल इसके प्रभाव को रेखांकित करती हैं: विद्या कार्यक्रम, जिसमें 14 साल तक की लड़कियों का नामांकन होता है, और प्रगति, जो 15-29 साल की किशोरियों और युवतियों को रोज़गार क्षमता बढ़ाने के लिए दूसरा अवसर प्रदान करता है।**

Key Points:-

(i) एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक सफीना हुसैन इस संस्था की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उनके नेतृत्व और नवाचार ने इस NGO को वैश्विक पहचान दिलाई है और भारत के बालिका शिक्षा आंदोलन को सुर्खियों में ला दिया है।

(ii) एजुकेट गर्ल्स अब प्रख्यात रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं की श्रेणी में शामिल हो गया है, जिनमें सत्यजीत रे और किरण बेदी से लेकर दलाई लामा और मदर टेरेसा तक के नाम शामिल हैं।

(iii) अपनी सफलता के आधार पर, एजुकेट गर्ल्स का लक्ष्य अगले दशक में 1 करोड़ शिक्षार्थियों तक पहुँचना है, जो राष्ट्रीय शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप होगा और सरकार व समुदायों के साथ साझेदारी का लाभ उठाएगा। इसका परिवर्तनकारी मॉडल स्थायी व्यवहार परिवर्तन और लैंगिक समानता पर ज़ोर देता है, और शिक्षा को एक मानवाधिकार

और सामाजिक न्याय के एक सशक्त साधन के रूप में सुदृढ़ करता है।

SUMMITS & CONFERENCE / COMMITTEES & MEETINGS

1. भारत-चीन संबंधों को फिर से मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग ने तियानजिन में SCO शिखर सम्मेलन 2025 में मुलाकात की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 31 अगस्त 2025 को चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में गलवान घाटी में तनाव के बाद संबंधों को बहाल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें संपर्क, सीमा स्थिरता, आर्थिक सहयोग और बहुपक्षीय जुड़ाव शामिल थे।

• 25वें SCO राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन चीन द्वारा 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक तियानजिन के मीजियांग कन्वेंशन सेंटर में किया गया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में भारत, रूस, पाकिस्तान और मध्य एशियाई देशों के नेताओं ने भाग लिया और यूरेशियाई सहयोग में SCO की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला।

• भारत और चीन सितंबर 2025 से सीधी वाणिज्यिक उड़ानें फिर से शुरू करने पर सहमत हुए, जो 2020 से निलंबित थीं, और लिपुलेख (उत्तराखंड), शिपकी ला (हिमाचल प्रदेश) और नाथू ला (सिक्किम) के माध्यम से सीमा व्यापार मार्गों को फिर से खोलने पर सहमत हुए। उन्होंने सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देते हुए 2026 में कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने की भी घोषणा की।

• दोनों पक्षों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के प्रबंधन के लिए नए संस्थागत तंत्रों पर सहमति व्यक्त की, जिसमें कमांडर-स्तरीय वार्ता और नदियों एवं संपर्क पर कार्यसमूहों का गठन शामिल है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री डोंग जून अपने-अपने मंत्रालयों के माध्यम से समन्वय की देखरेख करेंगे।

Key Points:-

(i) प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों, हरित ऊर्जा तथा दुर्लभ मृदा व्यापार में सहयोग की संभावनाओं पर ज़ोर दिया। राष्ट्रपति शी ने वैश्विक दक्षिण देशों की सहायता के लिए SCO विकास बैंक और नई वित्तीय प्रणालियों का प्रस्ताव रखा, जो बहुपक्षीय रणनीतियों में बदलाव का प्रतीक है।

(ii) बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत और चीन "प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि साझेदार हैं" जिसका उद्देश्य विवादों को व्यापक सहयोग को प्रभावित करने से रोकना है।

(iii) तियानजिन घोषणा और SCO विकास रणनीति 2035 को अपनाने से व्यापक कूटनीतिक पुनर्संयोजन का संकेत मिला, जिससे भारत-चीन-अमेरिका गतिशीलता को नया आकार मिला और एशिया के बहुपक्षीय ढांचे को मजबूती मिली।

IMPORTANT DAYS

1. संयुक्त राष्ट्र ने 31 अगस्त, 2025 को अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए 5वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया।

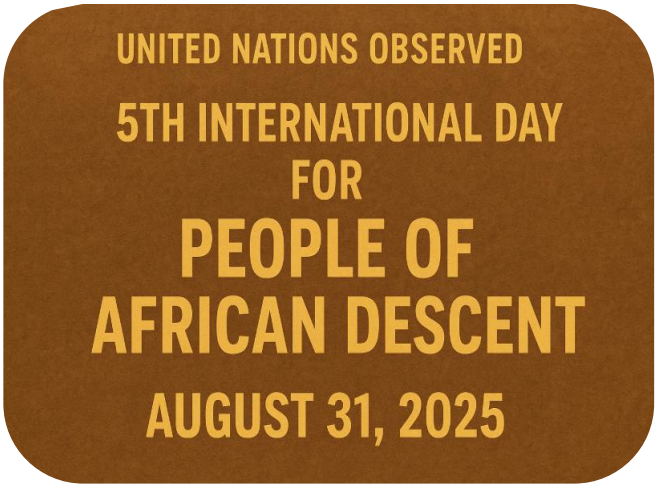

संयुक्त राष्ट्र (UN) ने 31 अगस्त 2025 को अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए 5वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। यह दिन अफ्रीकी मूल के लोगों के खिलाफ नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव और सभी प्रकार की असहिष्णुता का मुकाबला करते हुए वैश्विक स्तर पर अफ्रीकी प्रवासियों के योगदान को मान्यता देता है।

- **संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 16 दिसंबर 2020 को प्रस्ताव A/RES/75/170 को पारित किया, जिसके तहत हर साल 31 अगस्त को अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। समानता, न्याय और समावेशिता पर ज़ोर देने के लिए मध्य अमेरिकी राष्ट्र कोस्टा रिका ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था।**

- **पहला आयोजन 31 अगस्त 2021 को हुआ, जो यूनिवर्सल नीग्रो इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन (UNIA) द्वारा 1920 में आयोजित विश्व के नीग्रो लोगों के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के शताब्दी वर्ष के समापन का प्रतीक है। यह ऐतिहासिक जुड़ाव इस दिन को गहरा प्रतीकात्मक और सांस्कृतिक महत्व देता है।**

Key Points:-

(i) 2025 में पाँचवाँ समारोह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दशक (2025-2034) की शुरुआत के साथ मेल खाता है, जिसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2024 में "अफ्रीकी मूल के लोग: मान्यता, न्याय और विकास" विषय के अंतर्गत की थी। यह पहले दशक (2015-2024) पर आधारित है।

(ii) 2 अगस्त 2021 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीकी मूल के लोगों पर स्थायी मंच की स्थापना हेतु प्रस्ताव A/RES/75/314 को अपनाया। यह मंच वकालत, परामर्श और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली सहयोग के माध्यम से दुनिया भर में अफ्रीकी मूल के लोगों की सुरक्षा, आजीविका और जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(iii) यह दिवस प्रणालीगत नस्लवाद से लड़ने और अफ्रीकी मूल के लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, तथा वैश्विक विकास और मानव प्रगति में उनके विशाल सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक योगदान को स्वीकार करता है।

2. भारत 1-7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 मनाएगा।

भारत 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 मनाएगा, जिसका समन्वय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) के अंतर्गत खाद्य एवं पोषण बोर्ड (FNB) द्वारा किया जाएगा। यह सप्ताह स्वस्थ आहार

संबंधी आदतों के बारे में जागरूकता फैलाने, कुपोषण दूर करने और पोषण अभियान जैसी सरकारी प्रमुख योजनाओं के साथ तालमेल बिठाने पर केंद्रित है।

- **राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पहली बार 1982 में भारत सरकार द्वारा मनाया गया था, जो 1973 में अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन द्वारा शुरू किए गए एक ऐसे ही अभियान से प्रेरित था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में, विशेष रूप से बच्चों और माताओं में, बढ़ते कुपोषण संकट का समाधान करना और एक स्वस्थ, अधिक उत्पादक जनसंख्या का निर्माण करना था।**

- **इस पहल का नेतृत्व महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के सहयोग से कर रहा है। यह 2018 में शुरू किए गए एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS), मध्याह्न भोजन योजना और राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान) जैसे पोषण-आधारित सरकारी कार्यक्रमों से भी जुड़ा हुआ है।**

Key Points:-

(i) इस वर्ष का विषय है "बेहतर जीवन के लिए सही भोजन करें", जो संतुलित आहार, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से परहेज और स्थानीय रूप से उपलब्ध पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करने पर ज़ोर देता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी भारत में कुपोषण और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से लड़ने के लिए टिकाऊ और किफायती खान-पान की आदतों को बढ़ावा देना है।

(ii) इस सप्ताह के दौरान, स्कूल, कॉलेज और सामुदायिक केंद्र पोस्टर-मेकिंग, निबंध प्रतियोगिताएँ, पोषण विशेषज्ञों द्वारा कार्यशालाएँ, "स्वस्थ टिफिन दिवस" और स्वास्थ्य शिविर आयोजित करते हैं। ये कार्यक्रम बच्चों, अभिभावकों और स्थानीय समुदायों को शिक्षित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जागरूकता ग्रामीण और शहरी दोनों ही घरों में जीवनशैली में वास्तविक बदलाव ला सके।

(iii) राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भारत में कुपोषण के विरुद्ध लड़ाई को मज़बूत करने में एक रणनीतिक भूमिका निभाता है, जो NFHS-5 (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण) के अनुसार पाँच वर्ष से कम उम्र के 35% से अधिक बच्चों को प्रभावित करता है। जागरूकता अभियानों को नीतिगत पहलों के साथ जोड़कर, सरकार दीर्घकालिक लचीलापन बनाने और देश भर में जन स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने का प्रयास करती है।

Static GK

Indian Council of Agricultural Research- Central Marine Fisheries Research Institute (ICAR-CMFRI)	निदेशक : डॉ. ग्रिंसन जॉर्ज	मुख्यालय : कोच्चि (केरल)
Department of Posts (DoP)	सचिव: सुश्री वंदिता कौल	मुख्यालय: नई दिल्ली
Indian Army	थल सेनाध्यक्ष (COAS): जनरल उपेंद्र द्विवेदी	मुख्यालय: नई दिल्ली
RBI	राज्यपाल: संजय मल्होत्रा	मुख्यालय: मुंबई
Thailand	राजधानी: बैंकॉक	मुद्रा: थाई बाट
South Asian Football Federation (SAFF)	अध्यक्ष: काजी सलाहुद्दीन	मुख्यालय: ढाका, बांग्लादेश
Universal Negro Improvement Association (UNIA)	अध्यक्ष - स्टीफन गोल्डिंग	मुख्यालय - न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)
Zimbabwe	राजधानी: हरारे	अध्यक्ष: एमर्सन मनांगाग्वा
Ministry of Tribal Affairs (MoTA)	मंत्री: श्री जुएल ओराम	मुख्यालय: नई दिल्ली
China	राजधानी: बीजिंग	राष्ट्रपति: शी जिनपिंग
Ministry of Women & Child Development (MoWCD)	मंत्री: श्रीमती अन्नपूर्णा देवी	मुख्यालय: नई दिल्ली